

भारत सरकार  
अंतरिक्ष विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4400  
बुधवार, 20 अगस्त, 2025 उत्तर देने के लिए

नाविक नेविगेशन प्रणाली

**4400. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि देश के लोगों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित नेविगेशन प्रणाली नेविगेशन विद इंडियन कॉन्सटेलेशन ('नाविक') के बारे में बहुत कम पता है;
- (ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) सरकार द्वारा सभी फोनों के लिए जीपीएस की तरह 'नाविक' इनबिल्ट ऐप को अनिवार्य बनाने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) जीपीएस के निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए बाध्यकारी नहीं होने के दृष्टिगत सरकार 'नाविक' को जीपीएस के विकल्प के रूप में किस प्रकार प्रस्तुत करने की योजना बना रही है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय  
तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री  
(डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

\*\*\*\*

(क) एवं (ख)

देश के लोग नेविगेशन विद इंडियन कॉन्सटेलेशन (नाविक) प्रणाली के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं।

(ग) और (घ)

अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) विभिन्न क्षेत्रों में नाविक के उपयोग को व्यापक बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस दिशा में, विभाग ने पायलट परियोजनाएं, भारतीय उद्योग को प्रौद्योगिकी

..2..

हस्तांतरण, तकनीकी सहायता, परीक्षण सहायता, उपयोग कार्यक्रम आदि से संबंधित गतिविधियाँ शुरू की हैं। डीओएस ने नाविक को राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय उद्योग मानकों में शामिल करने के प्रयास किए हैं, जिससे उत्पादों और समाधानों में नाविक को दक्षता, सुसंगतता और निर्बाध रूप से अपनाया जा सके। एल1 आवृत्ति में एक नए संकेत का समावेश किया जा रहा है ताकि बड़े पैमाने पर बाजार में इसे तेज़ी से अपनाया जा सके। वर्तमान में विभिन्न निर्माताओं के 60 से अधिक स्मार्टफोन नाविक को सपोर्ट करते हैं।

\*\*\*\*